against the seventeen on-going medium irrigation projects was Rs. 483.17 crores. So, every effort is being made to complete these on-going projects so that the water can be made available for irrigation purpose; and increase the agricultural area of not only in the State of Jharkhand but also in other parts of the country.

श्री कृपाल परमार : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 69 नए प्रोजेक्ट, प्रोपोजल शूरू किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनमें से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कितनी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और उनके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, I need a separate notice for this question.

विदेशों की यात्र करने वाले प्रतिनिधिमंडल

*384. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :††**

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक सरकारी और गार-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशों की यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हैं, तो 200-2001,-2002 तथा 2002-2003 के दौरान ऐसे कितने-कितने प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों की यात्रा की थी; और

(ग) इन प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं पर वर्षवार किताना व्यय किया गया था?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" और श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछे गए मौखिक प्रश्न संख्या-384 के उत्तर में संभव विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सूचना का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) विदेश यात्रा के लिए निधियों का आबंटन और विदेश यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय के बारे में सूचना संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की विस्तृत अनुदान मांगों, जो कि वार्षिक रुप से सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है, में उपलब्ध है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।

Delegation visiting foreign countries

*384. SHRI RAJEEV RANJAN SINGH 'LALAN': ††
SHRI RAM JETHAMALANI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of official and non-official delegations visit foreign countries;

(b) if so, the number of such delegations that visited foreign countries during 2000-01,2001 -02 and 2002-03; and

(c) the expenditure incurred on the visits of these delegations, year-wise?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI JASWANT SINGH): A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) This information is not maintained centrally.

(c) Information regarding allocation of funds for foreign travel and actual expenditure on foreign travel is available in he Detailed Demands for Grants of respective Ministries/Departments, placed annually on the Table of the House.

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : सभापति जी, मेरा प्रश्न था कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने सरकारी और गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेश गए और उन पर क्या व्यय किया गया? जो सरकार का उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें है कि " The information is not maintained centrally" महोदय, जितने भी प्रस्ताव जिन-जिन विभागों से जाते हैं, वे वित्त विभाग में जाते हैं और वत्त विभाग की सहमति के बाद ही वह प्रतिनिधिमंडल विदेश जाता है। उसमें यह भी लिखा होता है कि किस हैड में कितना खर्च होना है और कितना इस पर खर्च होगा। अब उसके बाद यदि यह कहा जाए कि यह इन्फारमेशन मेंटन नहीं होता है तो हमको लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, सभापति महोदय, विदेश के दौरों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और मुझे लगता है कि यह सूचना को छिपाने का एक तरीका है कि This is not maintained centrally. इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब वित्त विभाग की सहमति के

†Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Rajeev Ranjan Singh 'Lalan'.

पश्चात् ही कोई डेलिगेशन या प्रतिनिधिमंडल विदेश में जाता है, उस स्थिति में वित्त मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है?

श्री जसवंत सिंहः सभापति जी, मुझे बेहद खेद है कि माननीय सदस्य को मुझे विाराश करना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय कुछ नहीं छिपाता और न ही छिपाने का प्रयत्न कर रहा है।

सभापति जी, यह प्रश्न बरसात के कीड़े की तरह है। हर तीसरे-चौथे महीने यह प्रश्न आता है। मैंने पिछले सालों के रिकार्ड देखे, छः सालों से यही सिलसिला चल रहा है। जब हमने इसका विश्लेषण किया कि क्या बात है तो पाया कि 1960 में एक मानसिक प्रवृत्ति बना थी, जब फॉरेन एक्सचेंज की बड़ी कमी थी, कि विदेश में जाना एक प्रकार का जधन्य अपराध था। चाहे देश का काम हो, नहीं हो, विदेश नहीं जाना चाहिए। इसकी वहां से उत्पत्ति हुई। फिर मैंने पाया कि इस सवाल में हर वक्त यही जवाब दिया जा चुका है क्योंकि यह सैंट्रली मैंटेन्ड नहीं होता है। राज्यों के भी डेलीगेशन है, केन्द्र के भी हैं, सभी मंत्रालयों के हैं, इसलिए हम इस प्रकार की हर जानकारी को वित्त मंत्रालय में केन्द्रित रूप में एकत्रित करके रखें ताकि हर तीसर-चौथे महीने इसका जवाब दिया जाए, यह संभव नहीं है। इस तरह का सवाल हर तीसरे-चौथे महीने पूछा गया है और यही उत्तर दिया गया है। हम हर तीसरे-चौथे महीने उसका उत्तर देते रहें, यह वित्त मंत्रालय के लिए संभव नहीं है। निश्चित रूप से यह हमारे पास स्वीकृति के लिए आता है, उसमें राज्यों के प्रस्ताव भी आते हैं, सब डेलीगेशंस के प्रस्ताव आते हैं, पर इस प्रकार की मानसिकता से हम पर हट जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर तीसरे महीने, चौथे महीने यह सवाल आ जाता है, इसलिए हम कोई सूचना नहीं छिपाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, मेरे प्रश्न के खंड "ग" को आप देखेंगे तो मैंने पूछा है कि उस पर कितना खर्च हुआ। अब उसकी भी सूचना वित्त मंत्रालय के पास नहीं है। वित्त मंत्रालय कहता है कि सभी कागजात सदन की टेबल पर रख दिए गए हैं, उसमें विभाग की Annual Report भी शामिल है, आप उसमें पढ़ लीजिए। अगर यही पढ़ना है तो लाईब्रेरी में सारी चीजें उपलब्ध हैं, हम लोग वहीं पढ़ लेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय अगर खर्चों पर नियंत्रण करता है और वित्त मंत्रालय का काम है खर्चों पर नियंत्रण करना तो ऐसे खर्च का ब्यौरा वित्त मंत्रालय क्यों नहीं रखता है?

श्री जसवंत सिंह : सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय जिस खर्च को आवश्यक समझता है, उस पर नियंत्रण रखता है। रेल का भाड़ा, हवाई-जहाज का भाड़ा, कहां जाना है, कहां नहीं जाना, इसका हिसाब रखना हम आवश्यक नहीं समझते। अपनी बुद्धि के अनुसार जिसे हम आवश्यक समझते हैं, जो जानकारी चाहिए हर मंत्रालय के बारे में, वह हम रखते हैं।

MR. CHAIRMAN: Shri Ram Jethmalani, absent.

प्रो. रामगोपाल यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का जो प्रश्न का जवाब था, वह तो निराशाजनक था ही और उन्होंने शुरू में ही कह दिया कि मैं सदस्य को निराश करूंगा। जैसा आप कह रहे हैं कि सन 1960 में जब फॉरेन एक्सचेंज की कमी हुआ करती थी, तब बाहर जाना एक अपराध-सा समझा जाता था, अब ऐसी बात नहीं है। अगर वित्त मंत्रालय की इतनी दखलंदाजी नहीं है तो क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री को आपने बाहर जाने से रोका था? जब बहुत शोर-शराबा हुआ, बहुत हल्ला हुआ, तब अनुमति दी गई। अगर कोई वजह हो सकती है जिसके कारण आप रोकते हैं यह कहकर कि पैसा खर्च होगा, यह होगा, वह होगा, तो उसे बताने में आपको क्या दिक्कत आ रही है?

श्री जसवंत सिंह : चूंकि माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा है, इसलिए मैं इसका उत्तर दे दूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री बाहर जाना चाहते थे। जैसे मुख्यमंत्रियों के बाहर के दौरे होते हैं तो पहली स्वीकृति Ministry of External Affairs से होती है क्योंकि उसका राजनीतिक रूप देखा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप देखा जाता है। इसके बाद दूसरी स्वीकृति होती है वित्त मंत्रालय से, यह देखने के लिए कि उनके साथ जो डेलीगेशन जा रहा है और जिस काम के लिए जा रहा है, उसके अनुरूप यह है या नहीं। अब रामगोपाल भाई ज्यादा डिटेल में न पुछें तो अच्छा रहेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ बहुत बड़ा डेलीगेशन था और वे Foreign hospitality के तहत जा रहे थे। अगर आपकी प्राइवेट विजिट हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। Foreign hospitality का मामला गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जहां चाहे सांसद हों, चाहे मंत्री हों, वे Foreign hospitality को स्वीकार नहीं कर सकते। यह आपका भ्रम है कि सरकार ने किसी प्रकार राजस्थान के मुख्य मंत्री को कहीं जाने से रोका। मैं आपको बता दूं कि यह फाईल मेरे पास वित्त मंत्रालय में दोपहर को शायद 2 बजे आई होगी और 2 बजकर 3 मिनट पर रवाना हो गई। उसके बाद आपका यह कहना कि ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : रवाना तो कर दी लेकिन आपने कोई ऑब्जेक्शन किया?

श्री जसवंत सिंह: कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने कहा कि आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। तो यह जो कमी इसे दूर कर लीजिए। मैंने तो इतने दिनों इस पर कहीं बाहर पब्लिकली कोई टिप्पणी इसलिए नहीं की कि अपने आप में मैं इसको इतनी हल्की बात समझता था। इतनी हल्की बातें वहां से हो रही थीं कि मैंने कहा छोड़िए, अब हम क्या कहें, 2 मिनट के भीतर यह फाईल वित्त मंत्रालय से चली गई। वित्त मंत्रालय ने कभी किसी मुख्य मंत्री को बाहर जाने से नहीं रोका। जब से मुझे यह नौकरी मिली है, मुझे तो याद नहीं आता कि हमने किसी को कहा हो की आप मत जाइए।

MR.CHAIRMAN: Next Question.